MR. SPEAKER: I will allow you, if time is there.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Mr. Sontosh Mohan Dev is there. He is also from Assam. (Interruptions)

SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Sir, ... (Interruptions)

SHRI BIRENDRA SINGH RAO: Please let me answer. (Interruptions)

SHRI SONTOSH MOHAN DEV: You have answered. (Interruptions) MR. SPEAKER: Please let him answer. (Interruptions)

SHRI BIRENDRA SINGH RAQ: Sir, they have time and again, repeatedly made the allegation that we have discriminated against West Bengal Government and secondly that they have furnished certificates up to 50 per cent or more of the foodgrains released. I have made it clear. (Interruptions) You were kind enough to give ample opportunity. There was even discussion for half an hour on this question. Sir, as I said, in the beginning of this year the quantity...

SHRI JYOTIRMOY BOSU: No, No. (Interruptions)

SHRI BIRENDRA SINGH RAO: Will you allow me to complete? (Interruptions) You don't want me complete because it does not suit you. (Interruptions) Sir, a quantity of 95,000 tonnes was carried over from the last year. In the beginning this year 20,000 tonnes were released further. That makes a total quantity of 1,15,000 tonnes, and up to August this year we have received utilisation certificates for only 45,000 and odd tonnes-I won't be precise, Sir. After that we have released a quantity of 30,000 more. That makes for this year, since the beginning of April, a total quantity of 1,45,000 tonmes for West Bengal and Sir, the Government of West Bengal very recently on the 10th of November they have sent a telex message stating that

53,000 tonnes-53,021 tonnes—has been utilised. Now these 53,000 tonnes cannot be 50 per cent of the total quantity of 1,45,000 tonnes. It is their own statement, and we are not bound to accept that because it should be in the form of utilisation certificate. But even their telex message received on the 10th of November states that they have not utilised up to 50 per cent. That is much less than the quantity required. Only 53,000 tonnes out of a total of 1,45,000 tonnes. That is the figure and I ...

MR. SPEAKER: Mr. Sontosh Mohan Dev.

SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Sir, the basic idea of the food for work programme is to help the rural people. In Assam, and the other North Eastern Region as a whole the rural people are suffering because of hartals and bandhs. So, I would like to request the hon. Minister since he has stated in his statement that Nameland, Manipur and Assam are is default about the utilisation: certificate in view of the present situation in Assam whether he will consider not being too rigid and give relaxation and issue more foodgrains to the whole of North Eastern Region so that the rural people can get some work in the development work.

MR. SPEAKER: The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUES TIONS

जोधपुर में गृक्ष्मतरंगीय प्रणाली परियोजना

*185. अर्थ हशो क्रिश्लेट : ध्यार द्धार मह्मी निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेगे:

(क) वया जोधपुर में सूक्ष्मतरगीय प्रणाली परियोजना ग्रौर उससे संब्द्ध केन्द्र ने कार्य ग्रारम्भ कर दिया है;

- (ख) यदि हां, तो इस परियोजना का कार्य कब प्रारम्भ किया गया था;
- (ग) उस पर कितना खर्च आएगा, उसके कब तक पूरा होने की संभावना है और इस समय उसकी प्रगति क्या है;
- (घ) राजस्थान में इस परियोजना के आरम्भ किये जाने के बाद से सूक्ष्मतरंगीय प्रणाली आरम्भ करने का कार्य देश के अन्य कौन-कौन से भागों में आरम्भ किया गया था। और इस बारे में अब तक हुई प्रगति का पूरा ब्यौरा क्या है;
- (ङ) जोधपुर में सूक्ष्मतरंगीय प्रणाली भौर उससे संबद्ध केन्द्र के चालू हो जाने से संचालन दक्षता में कितनी वृद्धि होने की संभा-वना है श्रौर जोधपुर का कौन-कौन से नगरों के साथ सीधा टेलीफोन संबंध हो जाएगा;
- (च) जोधपुर के महत्व को देखते हुए दूरसंचार के क्षेत्र में कौन-कौन सी भावी योजनाएं तैयार की गई है या विचाराधीन हैं?
- संचार मंत्रालय में राज्य मंत्रे (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां ।
- (ख) जोधपुर-म्रजमेर जयपुर चौड़ी पट्टी सूक्ष्म तरंग प्रणाली का कार्य स्रप्रैल, 1975 में चालू किया गया था।
- (ग) से (च). 166.68 लाख रुपये की लागत की जोधपुर-अजमेर-जयपुर चौड़ी पट्टी सूक्ष्मतरंग प्रणाली नयी दिल्ली-जयपुर-बंबई सूक्ष्मतरंग प्रणाली के संशोधित प्राक्कलन के हिस्से के बतौर मंजूर की गई थी। जोधपुर-अजमेर-जयपुर मार्ग पर सिविल निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ उपस्कर प्राप्त हो चुके हैं और समूची सप्लाई 1982-83 के दौरान प्राप्त होने की उम्मीद है। इस योजना के 1983 के दौरान पूरी हो जाने की संभावना है।

स्रप्रैल, 1975 में जोधपुर-स्रजमेर-जयपुर चौड़ी पट्टी सूक्ष्मतरंग प्रणाली शुरु करने के बाद निम्नलिखित चौड़ी पट्टी सूक्ष्म तरंग प्रणालियां कार्यान्वयन हेतु चालू की गई हैं:—

- (i) शिमला-ग्रम्बाला-ग्रमृतसर
- (ii) कलकत्ता-उत्तर बंगाल-ग्रसम
- (iii) मद्रास-जेलम-कोयम्बटूर-एर्ना-कुलम/सेलम-तिरुची-मदुरै
- (iv) नागपुर-सिकन्दराबाद-बंगलूर
- (V) मद्रास-खड़गपुर

इन संपर्कों की प्रगति से संबंधित वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

- (i) शिमला ग्रम्बाला ग्रमृतसर : सिविल निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ उपस्कर प्राप्त हो चुके हैं ग्रीर उपस्करों की पूर्ण सप्लाई 1982-83 के दौरान प्राप्त हो जाने की संभावना है।
- (ii) कलकता-उत्तर बंगाल-ग्रसम : कल-कता-कूच बिहार-शिलांग शाखा पर रेडियो उपस्कर की संस्थापना का कार्य पूरा हो चुका है । शेष शाखाग्रों ग्रर्थात् गोहाटी-जोर-हाट-तिनसुकिया का सिविल निर्माण कार्य चल रहा है । इस योजना हेतु मल्टीप्लिक्संग उपस्कर ग्रांशिक रूप से प्राप्त हो चुके हैं ग्रीर उपस्करों की समूची सप्लाई 1982-83 के दौरान प्राप्त होने की संभावना है ।
- (iii) मद्रास सेल्म कोयम्बर्र एर्नाकुलम / सेल्म तिरुची भदुरं : सिविल निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ग्रौर जब रेडियो उपस्कर की संस्थापना का कार्य चल रहा है। इस योजना हेतु मल्टीप्लिक्सिंग उपस्करों की ग्रांशिक सप्लाई प्राप्त हो चुकी है ग्रौर इस सप्लाई के उत्तरोत्तर रूप से 1981-82 ग्रौर 1982-83 के प्रारम्भ में ही पूर्ण हो जाने की संभावना है।
- (iv एवं v) नागपुर-सिकन्दराधाद-वंगलर: नागपुर-बंगलूर श्रीर मद्रास-खड़गपुर

सूक्ष्म तरंग दोनों योजनाम्रों पर सिविल-निर्माण कार्यं भ्रपनी प्राथमिक भ्रवस्था में है भौर उस पर कार्य चल रहा है। टावरों, पावर संयंत्र भौर रेडियो उपस्करों हेतु ब्रादेश दे दिए गए हैं।

जोधपुर-स्रजमेर-जयपुर चौड़ी पट्टी सूक्ष्म तरंग प्रणाली के पूरा होने के साथ ही जोधपुर को राष्ट्रीय ट्रंक जालकार्य से जोड़ने के लिए ग्रौर ग्रधिक ट्रंक सिंकट उपलब्ध होंगे। यह प्रस्ताव है कि प्रारम्भ में जोधपुर से राजस्थान के ग्रन्य महत्वपूर्ण शहरों जैसे जयपुर-कोटा, उदयपुर, ग्रलवर ग्रौर ग्रजमेर को एस० टी० ही० सुविधा प्रदान की जाएगी। यह सुविधा उत्तरोत्तर रूप से देश के ग्रन्य महत्वपूर्ण शहरों तक बढ़ाई जाएगी।

जोधपुर के ग्रनुकूल स्थितियों को मद्दे-नजर रखते हुए निम्नलिखित दूर संचार योज-नाएं तैयार की जा रही हैं/विचाराधीन हैं:—

- (1) जोधपुर-बलोत्ना -बाडमेर जैसल-मेर तंग पट्टी सहधूरीय केबुल प्रणाली ।
- (2) जोधपुर-पालीमरवार-फालना-सूमेरपुर-सिरोही-ग्राबू रोड-पालनपुर तंग पट्टी सहधूरीय केबुल प्रणाली ।
- (3) उपग्रह माध्यम द्वारा जोधपुर को ग्रन्य महानगरीय शहरों से जोड़ने हेतु जोधपुर में एक भू-उपग्रह केन्द्र ।
- (4) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान मौजूदा 5000 लाइनों का 8000 लाइनों में विस्तार।
- (5) 1981-82 के दौरान मंदौर (जोधपुर शहर) के मौजूदा एम ए एक्स II टेलीफोन एक्सचेंज का 200 लाइनों से 300 लाइनों में विस्तार।

(6) जोधपुर में 1000 लाइनों वाले ट्रंक स्वचल एक्सचेंज की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है।

Request for Funds for Drought Relief in M.P.

*188. SHRI DILEEP SINGH BHU-R!A: Will the Minister of AGRICUL-TURE be pleased to state:

- (a) the amount demanded by the Madhya Pradesh Government from the Central Government in 1979-80 and 1980-81 for providing drought relief in the State;
- (b) the amount sanctioned therefor under the non_Plan and Plan heads by the Central Government for these years; and
- (c) when the remaining amount on this account is likely to be paid to the Madhya Pradesh State?

THE MINISTER OF AGRICUL-TURE AND RURAL RECONSTRUC-TION AND IRRIGATION BIRENDRA SINGH RAO): During 1979-80 the Government Madhya Pradesh sought Rs. crores. During 1980-81 the State Government by their first Memorandum in April 1980, had sought Rs. 165.17 crores and by the Second Supplementary Memorandum dated the 10th November, 1980 have sought another Rs. 11 crores as Central assistance to meet the drought situation in that State.

(b) and (c) On the pasis of the reports of the Central Teams and the recommendations of the High Level Committee on Relief, the Government of India had approved so far the following ceilings of expenditure for purposes of Central assistance during 1979-80 and 1980-81:

Year							Non-Plan	Plan	Total (Rs. in crores)
1979-	-80		•	•	•	•	1.55	21.25	22 · 80
1980-	18-	•	•	•	•	•	4.26	43.64	47.90